

हरदिवार में पंचायत चुनाव पर वैधानिक संकट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरदिवार ज़िले में त्रसितरीय पंचायत चुनाव को लेकर वैधानिक संकट खड़ा हो गया है। पंचायतीराज एक्ट में संशोधन के बाद प्रशासकों का कार्यकाल छह माह और बढ़ाने के बाद भी वहाँ चुनाव की स्थिति नहीं बन पा रही है। राज्य गठन के बाद त्रसितरीय पंचायत चुनाव को लेकर ऐसी स्थिति पहली बार बनी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में हरदिवार ऐसा ज़िला है, जहाँ त्रसितरीय पंचायतों के चुनाव अन्य ज़िलों के साथ नहीं हो पाते। राज्य गठन के बाद से ही यह क्रम बना हुआ है।
- यहाँ पंचायतों का गठन अन्य ज़िलों से सालभर बाद होता है। इसी के चलते अक्टूबर 2019 में हुए पंचायत चुनावों में हरदिवार में चुनाव नहीं हो पाए थे। हरदिवार में पछिले पंचायत चुनाव वर्ष 2015 के आखिर में हुए थे। तब वहाँ 29 मार्च, 2016 को ग्राम पंचायतों, 16 मई को ज़िला पंचायत और 10 जून को क्षेत्र पंचायतों की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक के साथ ही पंचायतों का पाँच साल का कार्यकाल शुरू होता है, जो पछिले वर्ष खत्म हुआ।
- उत्तराखंड पंचायतीराज एक्ट, 2016 के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से 15 दिन पहले तक चुनाव न होने की स्थिति में उन्हें छह माह तक प्रशासकों के हवाले किया जा सकता है। इस क्रम में मार्च से हरदिवार ज़िले में त्रसितरीय पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किये गए। इस अवधि के भीतर भी चुनाव न हो पाने पर सरकार ने पंचायतीराज एक्ट में संशोधन कर प्रशासकों का कार्यकाल छह माह और आगे बढ़ाया।
- हरदिवार की 306 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल आगामी 29 मार्च को खत्म हो जाएगा। इस अवधि में भी चुनाव की स्थिति नहीं बन पा रही है, जिससे वैधानिक संकट खड़ा हो गया है। यद्यपि, विधानसभा चुनाव के लिये मतदान संपन्न होने के बाद शासन ने हरदिवार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के मद्देनज़र चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, लेकिन वह उसे नहीं मिला।
- राज्य के पंचायतीराज सचिव नतिश झा ने कहा कि हरदिवार ज़िले में पंचायत चुनाव न होने से वैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस सलिसलि में महाधिवक्ता और न्याय विभाग से राय ली जा रही है।